Date: July 29, 2025

To,

The Manager - Listing
Dept of Corp. Services,
BSE Limited
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001
Scrip Code: 543593

The Manager – Listing
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange plaza,Bandra Kurla Complex
Bandra East
Mumbai – 400 051
Symbol: DBOL

Dear Sir/Mam,

Sub: Newspaper Publication of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of Business Standard (English and Hindi both) dated July 29, 2025 wherein the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30, 2025 have been published.

You are requested to take note of the same.

Thanking you
Your Sincerely,
For Dhampur Bio Organics Limited

Ashu Rawat
Digitally signed by Ashu Rawat
Date: 2025.07.29 18:17:55 +05'30'

Ashu Rawat
Company Secretary & Compliance Officer

ट्रंप और विपक्ष के दावे खारिज

संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा : रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का विपक्ष पर तीखा हमला

अर्चिस मोहन

लोक सभा में सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का जवाब देते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फोटो-पीटीआई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को लोक सभा में जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय रक्षा बलों को सैन्य संपत्तियों का कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरह ही अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के उन दावों को भी खारिज कर दिया, जिनमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने का दावा किया था।

सिंह ने लोक सभा में दोपहर 2 बजे 'पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत का मजबूत, सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर' पर विशेष चर्चा शुरू की। विदेश मंत्री जयशंकर ने शाम को चर्चा में भाग लिया। जयशंकर ने कहा कि अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत में किसी भी स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर के साथ व्यापार का कोई संबंध नहीं था। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्रवाई रोकने का अनुरोध पाकिस्तानी पक्ष से आया था। विपक्ष द्वारा विदेश नीति की आलोचना का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि यह भारत की कूटनीति का ही परिणाम है कि पहलगाम आतंकी हमले के पीछे के आतंकी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को अमेरिका ने वैश्विक आतंकी संगठन के रूप में नामित किया।

जयशंकर ने कहा, '10 मई को हमें अन्य देशों की राय साझा करते हुए फोन कॉल आए कि पाकिस्तान लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। हम इस पर अडिग थे कि यदि पाकिस्तान तैयार है, तो वह डीजीएमओ चैनल से स्वयं अनुरोध करे। फिर वही हुआ।' उन्होंने कहा, 'मैं दो बातें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। एक, अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत में किसी भी स्तर पर व्यापार से कोई संबंध नहीं था। दूसरा, आतंकी हमले पर राष्ट्रपति ट्रंप के संवेदना व्यक्त करने के बाद 22 अप्रैल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई। इसके बाद केवल 17 जून को उन्होंने तब फोन किया जब प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में थे। ट्रंप ने उनसे पूछा था कि क्या वह उनसे मिल सकते हैं।'

चर्चा के दौरान कांग्रेस के गौरव गोगोई ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले को रोकने में सुरक्षा चूक के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। शाह मंगलवार को सदन को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के प्रमुख वक्ता के रूप में रक्षा मंत्री के बाद बोलते हुए गोगोई ने कहा कि गृह मंत्री को उन 'सुरक्षा चूक' की जिम्मेदारी लेनी चाहिए जिसके कारण पहलगाम आतंकी हमला हुआ। सदन में कांग्रेस के उप नेता गोगोई ने कहा कि आतंकी हमले के बाद से 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार आतंकवादियों को न्याय के कटघरे में नहीं ला पाई है। उन्होंने सरकार से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने भारतीय जेट विमानों को मार गिराया गया। युद्धविराम सुनिश्चित करने के लिए व्यापार को खतरे के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों का उल्लेख करते हुए गोगोई ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने ट्रंप के इस बयान की ओर इशारा किया कि संघर्ष के दौरान पांच जेट विमानों को मार गिराया गया था।

रक्षा मंत्री राजनाथ ने अपने घंटे भर के भाषण में कहा कि विपक्ष सही सवाल नहीं पूछ रहा है। सिंह ने कहा, 'सरकार से सवाल पूछना विपक्ष का काम है। हमारे विपक्षी सदस्य पूछते रहे कि हमारे कितने विमानों को मार गिराया गया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं पूछा कि हमारी सेना ने कितने पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया। यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो पूछें कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे किसी सैनिक को नुकसान हुआ है। जवाब है नहीं, हमारे किसी भी सैनिक को नुकसान नहीं हुआ।' राजनाथ सिंह के भाषण के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह जानना चाहा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका गया। उन्होंने पूछा, 'आपने सैन्य कार्रवाई रोकी क्यों?' उनके यह सवाल उठाते ही सत्ताधारी दल के सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गए। मंत्री ने कहा कि वह पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं और विपक्ष के नेता को उनका भाषण सुनना चाहिए। मंत्रियों ने 26/11 के आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार को और 2009 के शर्म-अल-शेख समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दोषी ठहराया। इस मुद्दे पर चर्चा मंगलवार को जारी रहेगी।

पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकी ढेर

जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के बाहरी इलाके के जंगलों में सेना के शीर्ष पैरा कमांडो ने सोमवार को पहलगाम आतंकवादी हमले के कथित मास्टरमाइंड और उसके दो साथियों को मार गिराया। सेना की इस कार्रवाई को बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड माना जा रहा सुलेमान उर्फ आसिफ उस समय मारा गया, जब सुरक्षा बलों ने एक तकनीकी संकेत मिलने के बाद 'ऑपरेशन महादेव' नाम से अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि यह तकनीकी संकेत एक ऐसे सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल का इशारा कर रहा था, जिसका उपयोग पहलगाम हमले के हमलावरों ने भी किया था। अधिकारियों के मुताबिक, आज सेना की कार्रवाई में मारे गए अन्य आतंकवादियों की पहचान जिब्रान (जो पिछले साल सोनमर्ग सुरंग हमले में कथित रूप से शामिल था) और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतकों में अधिकतर पर्यटक थे। इसके बाद सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचों के खिलाफ 7 मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था।

बिहार में मतदाता सूची प्रकाशन पर नहीं लगेगी रोक: अदालत

भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन अदालत ने निर्वाचन आयोग से भी कहा कि वह उसके पहले के आदेश का अनुपालन करते हुए बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए आधार और मतदाता पहचान पत्र को स्वीकार करना जारी रखे। दोनों ही दस्तावेजों के प्रामाणिक होने की धारणा है।

पीठ ने कहा, 'जहां तक राशन कार्ड का सवाल है, तो हम यह कह सकते हैं कि उसकी आसानी से जालसाजी की जा सकती है, लेकिन आधार और मतदाता पहचान पत्र की कुछ विश्वसनीयता है और उनके प्रामाणिक होने की धारणा है। आप इन दस्तावेजों को स्वीकार करना जारी रखें।'

एक गैर सरकारी संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि मतदाता सूची को अस्थायी तौर पर अंतिम रूप नहीं दिया जाना चाहिए और मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन पर अंतरिम रोक लगनी चाहिए। पीठ ने न्यायालय के पिछले आदेश पर गौर किया, जिसमें कहा गया था कि याची अंतरिम राहत के लिए अनुरोध नहीं कर रहे। पीठ ने कहा कि इसलिए अब ऐसा नहीं किया जा सकता तथा मामले का स्थायी निपटारा किया जाएगा।

पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को सभी पक्षों को सुनने के बाद अंतिम निर्णय लेगा। निर्वाचन आयोग

अदालत ने कहा कि वह मंगलवार को मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अंतिम निर्णय लेगी। शीर्ष अदालत के दो न्यायाधीशों के पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग जालसाजी के मामलों से एक-एक कर निपट सकता है, क्योंकि किसी भी दस्तावेज में जालसाजी की जा सकती है। अदालत ने 10 जुलाई को आयोग से कहा था कि वह विधान सभा चुनाव से पहले बिहार में चुनावी सूची के एसआईआर के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को स्वीकार्य दस्तावेजों के रूप में माने। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसके निर्देश का मतलब यह नहीं है कि आयोग को केवल इन दस्तावेजों के आधार पर किसी का भी नाम सूची में शामिल करना होगा।

अदालत ने कहा, 'आपने कहा है कि आपकी सूची विस्तृत नहीं है। यदि आपके पास आधार को रद्द करने का कोई अच्छा कारण है, तो आप ऐसा बिल्कुल करें, लेकिन इसका कारण बताना होगा।'

एक जवाबी हलफनामे में आयोग ने कहा था कि आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड को बिहार में चुनावी सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता पात्रता के प्रमाण के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये तीनों दस्तावेज मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान पात्रता को सत्यापित करने के लिए आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करते हैं।

शीर्ष अदालत आयोग के 24 जून के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जिनमें बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का आदेश दिया गया है।

नकदी विवाद में जांच को चुनौती देर से क्यों?

भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा कि उन्होंने अपने आवासीय परिसर के बाहरी हिस्से में स्थित कमरे से अधजली नकदी मिलने के बाद अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देने के लिए सोमवार तक का इंतजार क्यों किया। न्यायमूर्ति वर्मा के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से न्यायाधीशों ने कहा, 'क्या आप यह उम्मीद कर रहे थे कि निर्णय आपके पक्ष में आ जाए? आप एक संवैधानिक प्राधिकारी हैं। आप यह नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता।'

जब नकदी मिली थी तब वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अदालत को बताया कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना की तीन न्यायाधीशों की जांच रिपोर्ट पर आधारित सिफारिश उन्हें हटाने का आधार नहीं हो सकती। दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने यह भी तर्क दिया है कि एक मौजूदा न्यायाधीश का आचरण विधायी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सार्वजनिक चर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता। उनके मामले में एक संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन किया गया।

न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास पर नकदी मिलने के आरोपों के बाद तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर मिली नकदी का कोई हिसाब नहीं है और वह यह समझाने में भी असमर्थ रहे कि यह रकम कहां से आई। इस आधार पर उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई सही है।

सिर्फ 1.37% पात्र कर्मियों ने चुना यूपीएस का विकल्प

हर्ष कुमार

केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से केवल 1.37 प्रतिशत ने अब तक एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुना है। सोमवार को लोक सभा में एक लिखित उत्तर में वित्त मंत्रालय ने बताया कि 20 जुलाई, 2025 तक कुल 31,555 पात्र कर्मचारियों ने ही यह योजना अपनाई है। सरकार ने योजना के तहत अपने विकल्प चुनने की तारीख 30 जून से बढ़ाकर इसी साल सितंबर तक कर दी है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तयशुदा भुगतान करने के लिए यूपीएस का विकल्प दिया गया है। अगस्त 2024 में सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था, 'यूपीएस को केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा।'

इंटर्नशिप योजना में 4 गुना आवेदन

रुचिका चित्रवंशी

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की प्रायोगिक परियोजना में 327 कंपनियों द्वारा पेश 1.18 लाख रिक्तियों के लिए लगभग चार गुना आवेदन प्राप्त हुए हैं। लेकिन कंपनियों ने कुल 71,000 लाभार्थियों को प्रस्ताव दिए हैं। यह जानकारी कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने सोमवार को एक सवाल के जवाब में संसद को दी।

मल्होत्रा ने लोक सभा में एक लिखित जवाब में बताया कि परियोजना के दूसरे दौर में कुल आवेदनों में 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की तरफ से आए। इनमें से 16.8 प्रतिशत को इंटर्नशिप करने का प्रस्ताव दिया गया। पहले दौर में भागीदार कंपनियों ने 60,000 से अधिक युवाओं को 82,000 से अधिक इंटर्नशिप प्रस्ताव दिए थे। इनमें से 28,000 से अधिक ने इन्हें स्वीकार किया। इस दौर में 8,700 से अधिक उम्मीदवार इंटर्नशिप में शामिल हुए हैं।

दिव्या ने हम्पी को हरा कर जीता शतरंज विश्व कप

भारत की युवा शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख ने अपने करियर की सबसे बड़ी सफलता हासिल करते हुए सोमवार को यहां हमवतन और अपने से कहीं अधिक अनुभवी कोनेरू हम्पी को टाइब्रेकर में हराकर फिडे महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया। इस जीत से 19 साल की दिव्या ने न सिर्फ यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता बल्कि साथ ही ग्रैंडमास्टर भी बन गईं जो टूर्नामेंट की शुरुआत में असंभव लग रहा था। वह ग्रैंडमास्टर बनने वाली सिर्फ चौथी भारतीय महिला और कुल 88वीं खिलाड़ी हैं।

नागपुर की इस खिलाड़ी ने शनिवार और रविवार को खेले गए दो क्लासिकल मुकाबलों के ड्रॉ होने के बाद टाइब्रेकर में जीत दर्ज की। दो क्लासिकल बाजी ड्रॉ होने के बाद टाइब्रेकर का पहला समूह निर्णायक साबित हुआ, जिसमें हम्पी ने अपना संयम खो दिया। विश्व कप और महिला विश्व चैंपियनशिप को छोड़कर हम्पी ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज में सब कुछ जीता है।

दिव्या ने सोमवार को दृढ़ निश्चय दिखाया और इस जज्बे का बोनस ग्रैंडमास्टर खिताब था जो इस प्रतियोगिता के चैंपियन के लिए आरक्षित था। सोमवार को समय नियंत्रित टाइब्रेकर की पहली बाजी में सफेद मोहरों से खेलते हुए दिव्या ने हम्पी को फिर से ड्रॉ पर रोका लेकिन दूसरी बाजी में काले मोहरों से खेलते हुए उन्होंने दो बार की विश्व रैपिड चैंपियन को हराकर जीत दर्ज की। दिव्या अब हम्पी, डी हरिका और आर वैशाली के साथ देश की ग्रैंडमास्टर बनने वाली महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं।

हम्पी 38 साल की हैं और 2002 में ग्रैंडमास्टर बनीं, जबकि दिव्या का जन्म 2005 में हुआ। दिव्या ऊर्जा से भरी थीं और उन्होंने शुरुआती टाइब्रेकर में हम्पी पर दबाव बनाए रखा और अपनी दिग्गज प्रतिद्वंद्वी को थका दिया और फिर दूसरे टाइब्रेकर में जीत दर्ज की।

अपने से दोगुनी उम्र की प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ जीत के बाद भावुक दिव्या अपने आंसू नहीं रोक पाईं। दिव्या ने कहा, 'मुझे इस जीत को समझने के लिए समय चाहिए। मुझे लगता है कि यह नियति की बात थी कि मुझे इस तरह ग्रैंडमास्टर का खिताब मिला, क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले मेरे पास एक भी ग्रैंडमास्टर नॉर्म नहीं था और अब मैं ग्रैंडमास्टर हूं।' मुकाबले पर करीबी नजर रखने वाले पांच बार के पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने दिव्या की जीत की सराहना की और इसे भारतीय शतरंज के लिए महान जश्न करार दिया। आनंद ने 'एक्स' पर लिखा, 'दिव्या देशमुख को विश्व कप जीतने पर बधाई। **भाषा**

DHAMPUR BIO ORGANICS LIMITED

Regd. Office : Sugar Mill Compound, Village Asmoli Sambhal
Moradabad, UP - 244304 IN
CIN - L15100UP2020PLC136939, Phone No +91-7302318313
Email : investors@dhampur.com, Website - www.dhampur.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30-Jun-25 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)*	30-Jun-24 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)
1.	Total Income from Operations	785.26	703.80	638.62	2,696.64
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-32.96	60.57	0.72	17.47
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-32.96	60.57	0.72	15.71
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-22.00	44.80	0.12	14.69
5.	Total Comprehensive Income for the period	-22.05	46.12	0.17	16.72
6.	Paid up Equity Share Capital	66.39	66.39	66.39	66.39
7.	Other Equity				945.35
8.	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)				
	Basic & diluted (₹ per share)	₹ -3.31	₹ 6.75	₹ 0.02	₹ 2.21

*Refer note ii) below

Notes:

i) The above financial results are approved in the meeting of the Board of Directors held on July 28, 2025 after being reviewed and recommended by the Audit Committee.

ii) The figures for the quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the financial year.

iii) The Parent Company has its commercial papers listed on Bombay Stock Exchange with below details:
i) Credit Rating: Care A2+
ii) Outstanding amount as on June 30, 2025: ₹ 50 Cr
iii) Due date of repayment: August 12, 2025
iv) Actual date of repayment: N.A.
The additional information pursuant to regulation 52 (4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as applicable, in respect of commercial papers are disclosed in the full financial results submitted with stock exchanges.

iv) Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company.

v) Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever cosidered necessary.

vi) The consolidated financial results are available on the website of the Company (www.dhampur.com).
The specified items of the standalone financial results of the Company are given below:

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30-Jun-25 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)*	30-Jun-24 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)
Total Income	822.90	703.57	638.57	2,718.11
Profit before tax	-29.58	60.27	1.71	17.84
Profit after tax	-19.37	39.65	1.11	12.09

For Dhampur Bio Organics Limited
Sd/-
Gautam Goel
Managing Director & CEO
DIN 00076326

Place: New Delhi
Dated: July 28, 2025

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालयः केंद्रीकृत खरीद एवं भागीदारी प्रभाग
चौथी मंजिल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा की बाह्य लेखा परीक्षा करने के लिए बाह्य लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु आरएफपी

बैंक की आंतरिक लेखा परीक्षा की बाह्य लेखा परीक्षा करने के लिए बाह्य लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु पात्र बोलीदाताओं से GeM पोर्टल के माध्यम से खुली निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

अधिक जानकारी के लिए, इच्छुक बोलीदाता निविदा दस्तावेज (जीईएम बोली संख्या : **GEM/2025/B/6497813**) देख सकते हैं, जिसे बैंक के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल **https://etender.pnbnet.in** या बैंक की वेबसाइट **www.pnbindia.in.** से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

ई-निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 16.08.2025 को दोपहर 02:00बजे तक है।

मुख्य प्रबंधक

www.bankofbaroda.in बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

निविदा सूचना

बैंक ऑफ बड़ौदा, सूचना सुरक्षा विभाग, मुंबई, GeM पोर्टल के माध्यम से सिक्योर सॉकेट लेयर (SSL) ऑफ-लोडर समाधान की आपूर्ति, स्थापना और कार्यान्वयन के लिए बोलियाँ आमंत्रित करता है।

विवरण बैंक की वेबसाइट **www.bankofbaroda.in** के निविदा अनुभाग में उपलब्ध है।

निविदा में संशोधन सहित कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर ही अधिसूचित किया जाएगा। निविदाकर्ता अपनी निविदा जमा करने से पहले इसका संदर्भ लें।

GeM निविदा संदर्भ संख्या: GEM/2025/B/6488308

ऑनलाइन निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: **19-अगस्त-2025 को 15:00 बजे तक।**

स्थान : मुंबई
दिनांक: 29.07.2025
समूह मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी

55/25-26

ऑनलाइन शॉपिंग और भुगतान के लिए केवल विश्वसनीय वेबसाइट और एप्लिकेशन का ही उपयोग करें। प्रत्येक एप्लिकेशन के लिए एक विशिष्ट और जटिल पिन या पासवर्ड सेट करें।

It's money well spent

Tamil Nadu's MGNREGA efficiency outpaces bigger, poorer states

SHIKHA CHATURVEDI
New Delhi, 28 July

Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), passed by Parliament in August 2005 and implemented in a phased manner from February the next year, state governments are required to provide work within 15 days of demand or pay an unemployment allowance. This guarantees up to 100 days of wage employment annually to every rural household that demands it.

However, execution varies widely across states. It is influenced by local governance capacity, awareness among rural people, and the administrative infrastructure. Tamil Nadu stands out in this landscape. Despite being more urbanised and prosperous than states like Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, and Jharkhand, Tamil Nadu has consistently reported high fund utilisation and employment generation.

Unlike centrally allocated welfare schemes, the scheme is demand-driven, meaning funds are released based on the number of job requests raised by workers.

Over several financial years, the data shows that Tamil Nadu has received and utilised more funds than many larger and poorer states. This has triggered periodic accusations — particularly from Opposition parties and civil society groups — that the state is disproportionately cornering resources, raising concerns about whether wealthier and better-governed states are advantaged in what was meant to be an equity-oriented scheme. However, Tamil Nadu's performance aligns with its higher work-demand registration, efficient fund absorption, and better execution metrics — factors that are critical in a demand-based model.

On inquiry about this pattern, M Vijayabaskar, professor at the Madras Institute of Development Studies, said: "It's a function not just of economic status or the ability to claim work. Demand has to be expressed and translated through better political institutions that exist in states like Tamil Nadu and Kerala."

Fund releases and utilisation patterns

Between 2020-21 and 2023-24, Tamil Nadu received among the highest amount from the Centre. It got about ₹8,550 crore in 2020-21, increasing to about ₹12,140 crore by 2023-24. While Uttar Pradesh did lead in 2020-21 with ₹12,257 crore, Tamil Nadu overtook it in 2021-22 and remained close in following years. In contrast, Bihar, Madhya Pradesh, and Jharkhand consistently received lower allocations. For instance, Bihar received ₹6,647 crore in 2020-21, coming down to ₹6,238 crore in 2023-24, while Jharkhand's allocation too dropped from ₹3,490 crore in 2020-21 to ₹2,585 crore 2023-24 in the same years.

TAMIL NADU'S PERFORMANCE ALIGNS WITH ITS HIGHER WORK-DEMAND REGISTRATION, EFFICIENT FUND ABSORPTION, AND BETTER EXECUTION METRICS — FACTORS THAT ARE CRITICAL IN A DEMAND-BASED MODEL

The utilisation rates further reflect Tamil Nadu's administrative capacity. In 2023-24, it recorded a rate of 105.64 per cent, meaning it spent more than the funds released, relying partly on pending liabilities.

Madhya Pradesh followed closely at 105.48 per cent, while Bihar and Jharkhand achieved 98.84 per cent and 140.48 per cent, respectively. However, this utilisation often reflects how aggressively a state is able to demand funds and execute works. As regards 2025-26, although it is still early in the financial year, Tamil Nadu has utilised 40.38 per cent, the lowest among all the states.

Vijayabaskar said the real question was not just why Tamil Nadu was performing better but why states like Bihar and Uttar Pradesh were not able to translate demand into work.

"It's often the other way round — institutions in these states are unable to mediate or deliver on that demand," he added.

Completion rates

Another metric on which Tamil Nadu leads is project completion. In 2022-23, it reported a completion rate of 98.02 per cent, followed by 94.48 per cent in 2023-24. This is markedly higher than in other large states: Madhya Pradesh (67.51 per cent), Jharkhand (59.50 per cent), Bihar (53.70 per cent), and Uttar Pradesh (79.76 per cent). The high completion rate in Tamil Nadu points to a well-oiled administrative machinery. While some of this can be attributed to better planning and quicker approvals, it raises the issue of disparity in execution capacity, which could influence fund flows.

Employment days and persondays: Long-term gains

Over the past four years, Tamil Nadu has remained at the upper end in terms of average employment days provided per household, typically between 50 and 60 days.

In 2023-24, the state reported 59.44 days — ahead of Bihar (45.77), Jharkhand (50.22), Uttar Pradesh (50.37), and Madhya Pradesh (48.85). While Madhya Pradesh reported a peak of 61.84 days in 2020-21, Tamil Nadu has demonstrated more stable and consistent performance year after year.

In contrast, Tamil Nadu's record in generating persondays stands out not just for its consistency but also for its growth. It produced over 40.8 million persondays in 2023-24, its highest in four years, and maintained a stable range even in previous years. By comparison, Madhya Pradesh has shown a clear and steady decline — from 34.18 million in 2020-21 to just 19.96 million in 2023-24. This drop is particularly striking, given that states like Bihar (22.05 million) and Jharkhand (24.15 million) surpassed Madhya Pradesh in 2023-24, despite having smaller allocations or capacities. Uttar Pradesh has led consistently in absolute numbers, ranging between 39.3 million and 56.33 million annually.

Tamil Nadu's ability to generate high persondays despite a smaller rural population highlights the effectiveness of its decentralised planning, proactive mobilisation, and consistent fund utilisation. Unlike other states where distress often drives demand, Tamil Nadu's success appears rooted in administrative design and delivery.

Inclusion and participation: Women and marginalised groups

Tamil Nadu, under the MGNREGA, has consistently led the country in women's participation. Over the past four years, women have accounted for over 80 per cent of persondays in the state — peaking at 86.66 per cent in 2023-24.

PARTICIPATION BY SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES HAS BEEN MORE SUBDUED ACROSS ALL FIVE STATES

This contrasts sharply with Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, and Madhya Pradesh, where female participation has remained below 55 per cent each year.

"Agricultural work in Tamil Nadu is even more feminised now," Vijayabaskar noted.

"That reflects in the composition of workers, where older women have emerged as the most active demographic," he said.

Participation by Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs), however, has been more subdued across all five states. In Tamil Nadu, SC participation has remained relatively steady at around 27 per cent, while ST participation has stayed under 2 per cent — consistent with the state's demographic profile. Jharkhand and Madhya Pradesh report higher ST participation, exceeding 20 per cent and 30 per cent, respectively, but across the board, participation by marginalised castes has not shown any significant upward trend.

The data points to a broader implementation gap in ensuring that the MGNREGA reaches all eligible social groups at scale.

Tamil Nadu's trajectory in this underscores how state capacity can shape outcomes in a demand-driven welfare programme. Its consistent record across fund absorption, employment generation, and women's participation reflects the strength of its administrative machinery — from decentralised planning to local-level execution.

State of affairs

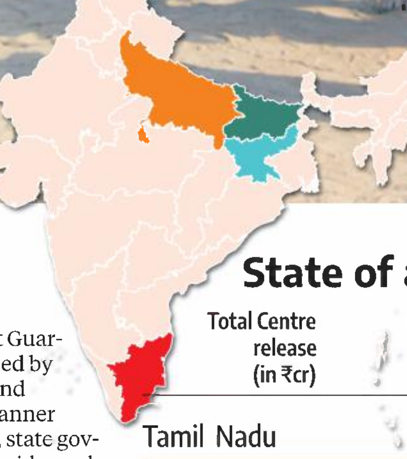

	Total Centre release (in ₹cr)	Utilisation (%)	Work completion rate (%)	Avg days of employment per household	Women persondays out of total (%)
Tamil Nadu					
FY21	8,549.89	92.1	NA	50.22	85.37
FY22	8,962.76	102.2	NA	50.95	85.7
FY23	9,727.88	100.28	98.02	50.96	86.42
FY24	12,136.33	105.64	94.48	59.44	86.66
FY25	7,587.59	125.61	74.09	46.86	86.28
FY26	4,354.16	40.38	15.69	11.09	85.58
Uttar Pradesh					
FY21	12,257.35	96.95	NA	41.84	33.57
FY22	8,493.38	100.09	NA	41.95	37.25
FY23	10,618.90	98.55	94.3	44.44	37.87
FY24	9,868.50	104.23	79.76	50.37	42.26
FY25	9,757.21	111.8	44.56	51.55	41.87
FY26	5,416.48	61.22	4.7	17.23	43.04
Bihar					
FY21	6,647.01	92.57	NA	44.65	54.63
FY22	5,460.43	91.55	NA	37.75	53.19
FY23	6,056.83	96.81	94.35	47.16	56.4
FY24	6,237.97	98.84	53.7	45.77	54.27
FY25	6,739.01	116.29	39.19	48.81	55.11
FY26	5,733.50	78.87	19.07	19.49	57.9
Jharkhand					
FY21	3,489.84	89.83	NA	46.35	42.56
FY22	2,724.56	111.9	NA	45.27	45.61
FY23	2,731.96	78.42	93.88	44.31	47.58
FY24	2,585.11	140.48	59.5	50.22	47.83
FY25	2,721.54	99.2	32.54	49.92	49.07
FY26	1,325.45	138	4.43	18.01	50.61

Note: FY26 numbers are till 26 July

Source: MGNREGA Dashboard

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

HO: CENTRALIZED PROCUREMENT & PARTNERSHIP DIVISION
FOURTH FLOOR, 5, SANSAD MARG, NEW DELHI 110001

RFP for appointment of External auditor to conduct external audit of Bank's Internal Audit System

Open tenders are invited from eligible bidders through GeM portal for appointment of External auditor to conduct external audit of Bank's Internal Audit System.

For further details, interested bidders may refer to the tender document (GeM bid no: **GEM/2025/B/6497813**) which can also be downloaded from Bank's e-procurement portal **https://etender.pnbnet.in** or from Bank's website **www.pnbindia.in.**

Last date of submission of the e-tender is 16.08.2025 up to 2:00 p.m.

CHIEF MANAGER

U. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD.
VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010
Ph. No. 0522-2307826/28 www.upsugcorp.in
Email : upstatesugarcorporation@gmail.com

Ref. No.: SS/SSC/Export/2024-25/436 Dated 28.07.2025

Tender Notice

Online e-Bids are invited from experience Export House/ Merchandise, Govt./Cooperative Institutions and such institutions having valid Importer/ Exporter code) **from 28.07.2025, 06:55 pm** to arrange purchase and export of sugar allotted for export from our units- Mohiuddinpur, (Distt. Meerut) Quantity- 17,130 Qtls. Pipraich, (Distt. Gorakhpur) Quantity-11,930 Qtls and Munderwa (Distt. Basti)) Quantity-13,510 Qtls. (Total Quantity 42,570 Qtls.) on "as is where is basis" as per stipulated norms. The last date of e-bid submission is **05.08.2025 upto 6:55 pm** and opening on **06.08.2025 on 12:00 Noon.**

Tender documents can be downloaded from e-tender **http://etender.up.nic.in** or Corporation website **www.upsugcorp.in.** Tender fees of Rs. 2000/- +18% GST= Rs. 2360/- and earnest money in the form of RTGS @ Rs. 100/- per quintal of bid quantity in favour of U.P. State Sugar Corporation Limited payable at Lucknow. Tenders without earnest money will not be accepted.

The undersigned reserves the right to cancel one or all the tenders without assigning any reason. **MANAGING DIRECTOR**

HINDUJA HOUSING FINANCE
HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
Corporate Office: Office No-286, 2nd Floor, Pocket-1, Sector-25, Rohini, New Delhi - 10085
Email: auction@hindujahousingfinance.com

ALM - Parmod Chand - 9990338759 • **RRM** - Pawan Kumar Pandey - 8010562716
CLM - Nidhi Juyal - 7292079861

Public Notice: Removal of Movable Items from Property

To, Date: 28.07.2025

1. **Mr. Amit Kumar (Borrower),** Plot No. C-173, Sector-7, JJ Colony, Pappan Kalan, Dwarka-110075
Mr. Amit Kumar, Pvt. Unit No- 303, Second Floor, (Front Middle Portion RHS), Plot Bearing No.- 3B & 4B, Tower-2, Khasra No. 590 & 631, Nawada Extension, Block B-4, Uttam Nagar, New Delhi-110059
2. **Mrs. Deepika Mehra (Co-Borrower),** Plot No. C-173, Sector-7, JJ Colony, Pappan Kalan, Dwarka-110075
Mrs. Deepika Mehra, Pvt. Unit No- 303, Second Floor, (Front Middle Portion RHS), Plot Bearing No.- 3B & 4B, Tower-2, Khasra No. 590 & 631, Nawada Extension, Block B-4, Uttam Nagar, New Delhi-110059

SUB:- Loan Account No. DL/DEL/DLHI/A000001626 & CO/CPC/CPOF/A000004210 of Mr. Amit Kumar

Dear Sir(s)/Madam(s),

The undersigned being the Authorized Officer of M/s Hinduja Housing Finance Limited hereby issue you this Notice as under:

1. That you had availed a credit facility of the nature 'Home Loan' for an amount of **Rs.24,00,000/- (Rupees Twenty Four Lakh only)** on **01.08.2022** and **Rs. 96,000/- (Rupees Ninety Six Thousand Only)** on 27-08-2024 from M/s Hinduja Housing Finance Limited (HHFL) and have executed a Loan Agreement and other relevant documents in our favour. You had also provided HHFL a security in the form of immovable property to secure the repayment of the loan granted to you and deposited with HHFL the title deeds of the said property more particularly described in schedule mentioned hereunder.
2. Consequent upon the defaults committed by you, your loan account was classified as Non-Performing Asset (NPA) on **06.03.2024** in accordance with the directives and guidelines issued by The Reserve Bank of India and subsequently Notice of Demand dated 02.07.2024 was issued by the undersigned against you under the provisions of Section 13(2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 ("the Act") and called upon you to pay in full and discharge your liabilities to Hinduja Housing Finance Limited (HHFL), aggregating **Rs. 24,98,720/- (Rupees Twenty Four Lakh Ninety Eight Thousand Seven Hundred Twenty Only)** as stated within 60 (sixty) days from the date of receipt of the notice.
3. That since you failed to pay the above said amount symbolic possession of the property was taken by HHFL by issuing Possession Notice dated **19.09.2024** under the provisions of section 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, against the Addressees with respect to the immovable property ('Secured Asset')as per schedule mentioned below and the said Notice was also affixed at the said property and further the Notice of possession was also published in the Daily Newspapers on **26.09.2024.** Thereafter the physical possession of the property was taken by the court appointed receiver on **28.03.2025.**
4. That subsequent to taking possession of the secured asset the same was put to symbolic e-auction vide a Notice dated **18-01-2025** published in the newspapers "Business Standard English" and "Business Standard-Hindi". The reserved price of the property was fixed for **Rs. 19,37,925/-.** A Notice of the sale of the below mentioned property was also issued to you the Addressees on **18-01-2025** thereby calling upon you to pay the outstanding amount of Rs. 24,98,720/-) as on 28-06-2024 within 15 days of the Notice, however you the Addressees did not make the said payment to HHFL. On **10-02-2025** i.e. the date of Auction no valid and qualified bids were received by HHFL against the secured asset.
5. That on the date of Sale Notice through Private Treaty i.e. **14-07-2025** HHFL received a successful and qualified bid and the property was sold for a sum of **Rs. 13,00,000/-.** Once the complete payment as mentioned above is received from the successful bidder/buyers of the property the same shall be adjusted against your outstanding dues as on the date of final realization of the amount. In case, upon adjustment and realization against your dues, if there is a surplus amount left the same shall be refunded to you and in the event there is a shortfall after realization of the sale amount against your loan dues then you the Addressees will be jointly and severally liable to pay the same.
6. That you the Addressees are further put to notice to collect your movable belongings kept in the said property, as per the inventory prepared by the court appointed receiver, on 04-08-2025 between 11 am to 4 pm from the said property. A copy of Inventory is being shared with you again along with this Notice. You may further note that in the event of failure on your part to collect the said articles the undersigned shall not be responsible in any manner whatsoever with regards to the health and maintenance of the said articles.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

Pvt. Unit No- 303, Second Floor, Without Roof/Terrace Rights, (Front Middle Portion RHS), Area Measuring 60 Square Yards, out of above-said Plot Bearing No.- 3B & 4B, Tower-2, of Khasra No. 590 & 631, situated in the revenue estate of village Nawada Extension, Block B-4, Uttam Nagar, New Delhi-110059.

BOUNDARIES: EAST- Back side Flat/ Other's Property; West- Road 16 feet; North- Main Entry/Road 18 feet; South- Other Property

Yours sincerely,
Authorized Officer, Hinduja Housing Finance Limited

DBO **DHAMPUR BIO ORGANICS LIMITED**
Regd. Office : Sugar Mill Compound, Village Asmoli Sambhal
Moradabad, UP - 244304 IN
CIN - L15100UP2020PLC136939, Phone No +91-7302318313
Email : investors@dhampur.com, Website - www.dhampur.com

Extract of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter ended June 30, 2025

(₹ in Crore)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended
		30-Jun-25 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)*	30-Jun-24 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)
1.	Total Income from Operations	785.26	703.80	638.62	2,696.64
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-32.96	60.57	0.72	17.47
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-32.96	60.57	0.72	15.71
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-22.00	44.80	0.12	14.69
5.	Total Comprehensive Income for the period	-22.05	46.12	0.17	16.72
6.	Paid up Equity Share Capital	66.39	66.39	66.39	66.39
7.	Other Equity				945.35
8.	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each)				
	Basic & diluted (₹ per share)	₹ -3.31	₹ 6.75	₹ 0.02	₹ 2.21

*Refer note ii) below

Notes:

i) The above financial results are approved in the meeting of the Board of Directors held on July 28, 2025 after being reviewed and recommended by the Audit Committee.

ii) The figures for the quarter ended March 31, 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the financial year.

iii) The Parent Company has its commercial papers listed on Bombay Stock Exchange with below details:
i) Credit Rating: Care A2+
ii) Outstanding amount as on June 30, 2025: ₹ 50 Cr
iii) Due date of repayment: August 12, 2025
iv) Actual date of repayment: N.A.
The additional information pursuant to regulation 52 (4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as applicable, in respect of commercial papers are disclosed in the full financial results submitted with stock exchanges.

iv) Sugar being a seasonal industry, the performance of the quarter may not be representative of the annual performance of the Company.

v) Figures for the previous corresponding periods have been regrouped, wherever cosidered necessary.

vi) The consolidated financial results are available on the website of the Company (www.dhampur.com).
The specified items of the standalone financial results of the Company are given below:

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30-Jun-25 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)*	30-Jun-24 (Unaudited)	31-Mar-25 (Audited)
Total Income	822.90	703.57	638.57	2,718.11
Profit before tax	-29.58	60.27	1.71	17.84
Profit after tax	-19.37	39.65	1.11	12.09

For Dhampur Bio Organics Limited
Sd/-
Gautam Goel
Managing Director & CEO
DIN 00076326

Place: New Delhi
Dated: July 28, 2025